पुराने मुस्तफाबाद इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या

हमलावर की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें की गई तैनात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के पुराने मुस्तफाबाद इलाके में 24 वर्षीय युवक की शुक्रवार को एक अज्ञात हमलावर ने कथित रूप से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान बाबू नगर निवासी साजिद उर्फ आलू दादा के तौर पर हुई है और उसका आपराधिक इतिहास था।

पुलिस के एक अधिकारी बताया कि शाम करीब छह बजे दयालपुर थाने को सूचना दी कि गई पुराने मुस्तफाबाद में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है और उसका जानकार उसे गुरुतेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले गया है जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनके मुताबिक, पुलिस की एक टीम ने पुराने मुस्तफाबाद में अपराध स्थल का निरीक्षण किया और अपराध व फारेंसिक टीमों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और महत्त्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए। उन्होंने बताया कि दयालपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि सत्यापन के दौरान पता चला कि युवक साजिद उर्फ आलू दादा का आपराधिक इतिहास था। अधिकारी ने बताया कि हमलावर की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। मामले की आगे की जांच जारी है।

पुलिस की एक टीम ने पुराने मुस्तफाबाद में अपराध स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए।

जहांगीरपुरी में हमले के बाद व्यक्ति की मौत, तीन किशोरों को पकड़ा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में छह महीने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए 23 वर्षीय व्यक्ति की कथित रूप से हत्या कर दी गई। इस बाबत पुलिस ने तीन किशोरों को पकड़ लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि व्यक्ति पर विवाद को लेकर हमला किया गया था जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

अधिकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह हमला उत्तर पश्चिम दिल्ली में लगभग छह महीने पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए किया गया था। आरिफ की मौत के बाद, उसके परिवार के सदस्यों और निवासियों ने कड़ी कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पुलिस ने कहा कि घटना को लेकर जहांगीरपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारी ने कहा कि अब तक तीन किशोरों को पकड़ा जा चुका है, जबकि शेष आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है।

अधिकारी के मुताबिक, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमला उत्तर पश्चिम दिल्ली में लगभग छह महीने पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए किया गया था। परिवार के सदस्यों और निवासियों ने कड़ी कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

तीन माह के खाद्यान्न की आपूर्ति एक साथ करने में होगी परेशानी

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

राशनकार्डधारियों को राशन दुकानों में चक्कर लगाने से मुक्ति दिलवाने व मानसून के दौरान भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के गोदामों में भंडारण की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त, सितंबर व अक्तूबर के राशन की एक साथ आपूर्ति व वितरण का आदेश दिया है। लेकिन दिल्ली में यह व्यवस्था पूरी तरह फेल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि एफसीआइ गोदामों से राशन दुकानों तक खाद्यान्न आपूर्ति करने का कार्य दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी) का है जोकि कम ट्रक व मजदूरों के चलते लचर तरीके से काम कर रही है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को 31 अगस्त तक एफसीआइ गोदामों से खाद्यान्न का उठान करने के साथ ही वितरण भी करना होगा। जिसके लिए तीनों महीने के खाद्यान्न का मासिक कोटा भी प्रत्येक राशन दुकानों के अनुसार आबंटित भी कर दिया गया है। जबकि असलियत यह है कि डीएससीएससी के द्वारा नियुक्त ट्रांसपोर्टरों के पास तीन गुना राशन उठाने के लिए पर्याप्त संख्या में न तो ट्रक हैं और ना ही मजदूर। वहीं दिल्ली में यातायात जाम की समस्या बारिश के दौरान बढ़ जाती है और कई बार एक ट्रक पूरे दिन में एक ही चक्कर लगा पाता है। वहीं अगस्त में साप्ताहिक अवकाश के अलावा राजपत्रित अवकाश भी हैं, जिससे खाद्यान्न उठान के लिए कम दिन मिलेंगे। डीएससीएससी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि अभी हम बड़ी मुश्किल से जुलाई का नियमित खाद्यान्न आपूर्ति 15 जुलाई तक कर पाएं हैं। इसके बाद 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' (ओएनओआरसी) के तहत खाद्यान्न आपूर्ति बुधवार से शुरू की गई है। ऐसे में तीन महीने का एकसाथ राशन उठान बहुत मुश्किल है।

बता दें कि, अप्रैल से जून माह के दौरान भी अग्रिम राशन वितरण करवाया गया था, लेकिन कई कार्डधारियों को अप्रैल व मई के महीने में अपने राशन से वंचित रहना पड़ा था। बारिश के मौसम में कीड़े लगने का डर रहता है, ऐसे में तीन महीने का अग्रिम राशन लेना लाभार्थियों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा व चूहों की समस्या बनी रहेगी। डीएससीएससी की लचर व्यवस्था इससे भी जान सकते हैं कि इसी वर्ष अप्रैल से जून 2026 का एक साथ उठान व वितरण का आदेश केंद्र सरकार ने दिया था। लेकिन अव्यवस्था के चलते विभाग की वेबसाइट के अनुसार अप्रैल माह का खाद्यान्न 10 अप्रैल, मई माह का 10 जून व जून माह का 24 जून तक राशन उठान किया गया।



केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को 31 अगस्त तक एफसीआइ गोदामों से खाद्यान्न का उठान करने के साथ ही वितरण भी करना होगा।

अल फलाह विवि के अध्यक्ष जवाद सिद्दीकी को नहीं मिली जमानत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने धन शोधन के दो मामलों में जेल में बंद अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने सिद्दीकी को 'कस्टडी पैरोल' पर तीन अलग-अलग तारीख को अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं।

सिद्दीकी ने यह बताते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था कि उनकी पत्नी की हालत गंभीर है और वह उनके जीवन के इस मुश्किल समय में साथ रहना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है। अदालत ने यह भी कहा कि उपलब्ध मेडिकल रिकार्ड के अनुसार उनकी पत्नी की हालत बिगड़ने के बजाय सुधर रही है। न्यायमूर्ति बनर्जी ने यह भी कहा कि सिद्दीकी के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने 13 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि हालांकि, अदालत याचिकाकर्ता की पत्नी के स्वास्थ्य की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है, लेकिन याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की गंभीरता और प्रकृति, मामले की वर्तमान कार्यवाही की स्थिति तथा उनके पद और प्रभाव को देखते हुए उसका स्पष्ट रूप से मानना है कि केवल मानवीय आधार पर जमानत प्रदान करने संबंधी वैधानिक प्रावधानों को शिथिल नहीं किया जा सकता।

'गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है भाजपा'

नई दिल्ली, 17 जुलाई (संवाददाता)।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भाजपा और मोदी-योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी-योगी-भाजपा का एक ही नारा है कि अनपढ़-गंवार रहेंगे बच्चे, तभी तो अंधभक्त बनेंगे बच्चे।

चौथी पास राजा और उसकी पार्टी भाजपा स्कूल, कालेज तोड़ने वाली पार्टी है। ये गरीबों के बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहती है। जिससे वह सवाल ना कर सके। अब ये लोग जौहर विश्वविद्यालय तोड़ने जा रहे हैं, जहां हिंदू-मुस्लिम सभी वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

पहले और तीसरे शनिवार को नहीं होगी सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अदालत में सुनवाई के अपने फैसले को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट प्रशासन ने एक अधिसूचना में कहा कि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय द्वारा गठित एक समिति इस मुद्दे पर विचार करेगी।

अधिसूचना में कहा गया कि नौ जुलाई 2026 को हुई पूर्ण पीठ की बैठक में फैसला किया गया कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अदालत में कामकाज का दिन घोषित करने संबंधी पूर्ण पीठ के 22 दिसंबर 2025 के पूर्व निर्णय को फिलहाल लागू नहीं किया जाए। यह निर्णय 15 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया था। इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति विचार करेगी। इससे पहले हाई कोर्ट प्रशासन ने 15 जनवरी को अधिसूचना जारी कर कहा था कि 22 दिसंबर 2025 को पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अदालत में कामकाज होगा। इस फैसले से पहले हाई कोर्ट में शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन काम होता था। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया था और वकीलों से इन दोनों शनिवार काम नहीं करने का आह्वान किया था। एसोसिएशन ने कहा था कि पहले और तीसरे शनिवार को अदालत में कामकाज होने से गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी।

यह निर्णय 15 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया था। इस मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित समिति विचार करेगी।

महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, साधना हाउस, दूसरी मंजिल, 570, पी.बी. मार्ग, वर्ली, मुम्बई 400 018
दूरभाष : 22 66523500, **फैक्स** : +9122 24972741
क्षेत्रीय कार्यालय : 35 जी/9 रामपुर गार्डन, रश्मि गोयल अस्पताल के पीछे, बरेली-243001

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेतु) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके पश्चात "एमआरएचएफएल" सन्दर्भित), जिसका पंजीकृत कार्यालय लखनऊ में तथा शाखा कार्यालय कानपुर में है, का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते आप कर्जदारों (नाम और पते नीचे उल्लिखित) को कथित सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक माँग सूचना निर्गत की थी।

यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदारों को एवं जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा/सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से यहाँ ऊपर उल्लिखित कर्जदारों को एवं जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए लिए मैसर्स महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/जमानती(यों) के नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	माँग सूचना की तिथि एवं राशि	कब्जे की तिथि
1.	बरेली शाखा **लैनः-1387194/ XSEMHLD01072235** **सतीश चंद्रा** (कर्जदार) **स्वाति स्वाति,** **रवि कुमार** (सह-कर्जदार)	खसरा नंबर 26/2 मिन. का हिस्सा, गाँव लूटाबाढ़, परगना भवर चिल्क्या, तहसील रामनगर, नैनीताल, उत्तरांचल - 244715, पूर्वः 16 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः विक्रेता की जमीन, उत्तरः विक्रेता की जमीन, दक्षिणः विक्रेता की जमीन	20-06-2025 रु. 10,29,903.59/-	17/07/2026 सांकेतिक कब्जा

स्थान : बरेली, तिथि : 18.07.2026 हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी, महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वन महोत्सव के दौरान देशज प्रजातियों के पौधे लगाएगी सरकार : सिरसा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली के पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शुक्रवार को दिल्ली रिज क्षेत्र के पीबीजी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान का नेतृत्व किया।

इस कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सिरसा ने कहा कि दिल्ली इस समय अपने सबसे बड़े पौधरोपण अभियानों में से एक की गवाह बन रही है, जिसके तहत इस साल पूरे शहर में 70 लाख पेड़ और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए रिज और अन्य चिह्नित हरित क्षेत्रों में 15 लाख पेड़ और पौधे लगाए जा रहे हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लगाए गए हर पेड़ की जियो-टैगिंग के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से निगरानी की जाए और लंबे समय तक उसकी देखभाल की जाए। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी हरित विरासत का निर्माण कर रहे हैं।

महरौली में युवक की मौत, परिजनों ने हिरासत में पिटाई का आरोप लगाया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

महरौली में पुलिस की कथित हिरासत से छुटने के बाद 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई और इसे लेकर उसके परिवार ने पुलिस कर्मियों पर हिरासत में प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस अधिकारियों ने आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि मौत तो या प्राकृतिक कारण से हुई है या पुरानी बीमारी इसकी वजह है।

अब एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपों की तफ्तीश के लिए सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। परिवार के मुताबिक, महरौली पुलिस ने 14 जुलाई को आसिफ और उसके भाई को छत्तरपुर पहाड़ी स्थित उनके घर से हिरासत में लिया और थाने ले गई।

परिवार ने दावा किया कि जब आसिफ थाने से घर लौटा तो वह बेहोश हो गया, उसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025, **सीआईएनः U65900DL2020PLC366027**

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 से ऋण सुविधा प्राप्त की है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज सर्व करने में विफल रहे हैं और यह कि उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्जदारों ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अब तक के ऋण और बकाया राशि तथा कर्जदारों द्वारा देय राशि का विवरण नीचे उल्लेख किया गया है :

कर्जदार/सह-कर्जदारों के साथ-साथ आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत प्रतिभूत लेनदार शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों के विरुद्ध निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्नलिखित कर्जदार इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने इंगित बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बेचने की शक्ति सहित प्रतिभूत लेनदार को प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक या उससे अधिक का प्रयोग करेंगे। आम तौर पर जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति का लेन-देन न करें।

कर्जदारों/जमानती तथा बंधककर्ता का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण
1. श्री आशुतोष भारद्वाज उर्फ आशुतोष शर्मा पुत्र श्री विजेंद्र कुमार भारद्वाज उर्फ वजेंद्र कुमार शर्मा (कर्जदार), निवासी 19, रामापुरम कॉलोनी, क्लाउड 9, कुटी चौराहा, अंसल रोड, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250004, इसके अलावाः 460, सेक्टर 13, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, आरटीओ के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250002, 2. श्रीमती प्रीति भारद्वाज उर्फ ??प्रीतल शर्मा पत्नी श्री आशुतोष भारद्वाज उर्फ ??आशुतोष शर्मा (सह-कर्जदार/बंधककर्ता), निवासी 19, रामापुरम कॉलोनी, क्लाउड 9, कुटी चौराहा, अंसल रोड, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250004, इसके अलावाः 460, सेक्टर 13, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर, आरटीओ के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250002, 3. श्री गौतम सिंह पुत्र छियादा सिंह (गारंटर), निवासी एम-658, गंगा नगर, मवाना रोड राजपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250001, पता भीः निवासी 48, गांव और पोस्ट लिसाड़ी, मेरठ, यूपी, 250002, पता भीः निवासी 189, पुरानी मोहन पुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250001, 4. श्री योगिंदर सिंह पुत्र श्री सुंदर सिंह (गारंटर), निवासी मकान नं. बी-37, यूरोपियन एस्टेट, बेस्ट प्राइस के पास, मेरठ, उत्तर प्रदेश, इसके अलावाः हाउस नंबर 188, गंगा नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250001	दृष्टिबंधकः सम्पत्ति पर इक्विटेबल बंधकः कुल 167.22 वर्ग मीटर एरिया वाला आवासीय प्लॉट; जो प्लॉट नंबर 19, खसरा नंबर 6292, रामापुरम कॉलोनी, क्लाउड 9, कुटी चौराहा, अंसल रोड, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 250004 पर स्थित है। यह श्रीमती प्रीति भारद्वाज पत्नी श्री आशुतोष भारद्वाज के नाम पर है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः 30 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः प्लॉट नंबर 20, उत्तरः 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर 18.

ऋण खाता सं., मांग सूचना की तिथि तथा राशि : ऋण खाता सं. 100841005784, 100846511095, मांग सूचना की तिथि : 17.07.2026
बकाया राशि : रु. 8,40,000/- (रुपये आठ लाख चालीस हजार मात्र)
एनपीए की तिथिः 30-06-2026

तिथि : 17.07.2026 स्थान : नोएडा अधिकृत प्राधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

एबीवीपी ने की सीटें बढ़ाने की मांग

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को छात्र कैंपस में सड़क पर उतरे। एक वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटों की पर्याप्त संख्या न होने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कैंपस में प्रदर्शन हुआ। जिसके बाद डीयू रजिस्ट्रार प्रो विकास गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों के विद्यार्थियों ने सहभागिता कर विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल सीटों में वृद्धि की मांग की।

डीयू : पहले राउंड में 66,000 छात्रों ने सीटें मंजूर की

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की पहली सूची जारी होने के एक दिन के भीतर ही 66,000 से ज्यादा छात्रों ने सीटें मंजूर कर ली। विश्वविद्यालय के अनुसार कामन सीट एलोकेशन सिस्टम के तहत पहली सूची जारी होने के एक दिन के अंदर ही 66,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने उन्हें मिली स्नातक सीटों को मंजूरी दे दी है।शुक्रवार तक 66,251 उम्मीदवारों ने सीटों को मंजूरी दे दी।

फॉर्म ए

सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत)

एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	**एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24/10/1961
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनियों के रजिस्ट्रार- यूपी-।।
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित देयता कॉर्पोरेट देनदार की पहचान संख्या	U21011UP1961PLC002861
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत पताः** मंसूरपुर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश-251203 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 59/15 सत्यम हाउस- ग्राउंड फ्लोर, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी एक्सटेंशन, दिल्ली-110019
6.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन प्रारंभ होने की तारीख	14.07.2026 (आदेश की प्रति 16.07.2026 को प्राप्त हुई)
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की अनुमानित तारीख	12/01/2027 (16.07.2026 को आदेश प्राप्त होने की तिथि से)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नामः पवन गर्ग पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N01011/2020-2021/13267
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता और ईमेल, जैसा कि बोर्ड के पास पंजीकृत है	पताः 14054, एटीएस वन हैमलेट, सेक्टर 104, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304 ई-मेल आईडीः cspawan.garg@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	पताः 14054, एटीएस वन हैमलेट, सेक्टर 104, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304 ई-मेल आईडीः svpind.cirp@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30/07/2026 (16.07.2026 को आदेश प्राप्त होने की तिथि से)
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई हों, सुनिश्चित की गई हैं	उपलब्ध नहीं है।
13.	एक वर्ग के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए नामित दिवालियापन पेशेवरों के नाम। (प्रत्येक वर्ग के लिए तीन नाम)	उपलब्ध नहीं है।
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है:	(क) वेब लिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads **भौतिक पताः** उपरोक्त बिंदु संख्या 10 के समान (ख) :उपलब्ध नहीं है।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने 14/07/2026 को एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 16.07.2026 को प्राप्त हुई)।

एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेनदारों को एतद् द्वारा आह्वान किया जाता है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 30/07/2026 तक प्रविष्टि संख्या 10 के समक्ष उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रस्तुत करें।

वित्तीय लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावे प्रमाण सहित व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

प्रविष्टि संख्या 12 में सूचीबद्ध वर्ग से संबंधित वित्तीय लेनदार, प्रपत्र ब। में अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि संख्या 13 में सूचीबद्ध तीन दिवाला पेशेवरों में से अपनी पसंद के अधिकृत प्रतिनिधि का चयन दर्शाएगा, जो स्वर्ग निर्दिष्ट करें, वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। झूठे या भ्रामक दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड आकर्षित होगा।

हस्ताक्षर/- पवन गर्ग
अंतरिम समाधान पेशेवर
एसवीपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N01011/2020-2021/13267
पंजीकृत पताः 14054, एटीएस वन हैमलेट, सेक्टर 104, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201304
ई-मेल आईडीः cspawan.garg@gmail.com, svpind.cirp@gmail.com

दिनांकः 18.07.2026
स्थानः नोएडा

दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव 27 को

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) अपनी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 27 जुलाई को चुनाव कराएगा। शुक्रवार को जारी एक नोटिस में यह जानकारी दी गई।

नोटिस में कहा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद यह चुनाव कराना जरूरी हो गया है। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया 15 जुलाई को पूरी कर ली गई। फिलहाल, वार्ड 226 (गौतम पुरी) का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्षद सत्या शर्मा (भाजपा) दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष हैं। शर्मा ने जून 2025 में हुए चुनाव के बाद एमसीडी स्थायी समिति की अध्यक्ष का पद संभाला, जिससे नगर निगम की मुख्य निर्णय लेने वाली शाखा पर भाजपा का नियंत्रण मजबूत हुआ। अपनी मौजूदा कार्यकारी भूमिका से पहले, उन्होंने 2023 की शुरुआत में महापौर पद के बेहद हंगामेदार चुनावों के दौरान पीठासीन अधिकारी के रूप में काम किया था।

निगम की 18 सदस्यों वाली स्थायी समिति वित्तीय निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक के बड़े वित्तीय फैसलों, अनुबंधों, नीतिगत मामलों और नागरिक परियोजनाओं को मंजूरी देती है। फिलहाल, समिति में सभी 18 सदस्य हैं, जिनमें 12 भाजपा और छह आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। बुधवार तक, समिति मार्च से केवल 12 सदस्यों के साथ काम कर रही थी क्योंकि छह खाली सीटों के लिए चुनाव लंबित थे, जिन्हें उसी दिन भरा गया।

समिति में 18 सदस्य हैं, जिनमें 12 भाजपा और छह आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं।

एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सीएंडबी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स,गांव चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059

**कब